पांच जिलों में 4500 करोड़ निवेश, 6000 को रोजगार

पहली बार पांच प्रस्तावों में 100 फीसदी ऑनलाइन प्रक्रिया

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति का असर दिखने लगा है। पांच जिलों में 4500 करोड़ रुपये के निवेश को शासन की मंजूरी मिल गई है। खास बात ये है कि आवेदन से लेकर स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया आनलाइन हुई है। इस निवेश से करीब 6000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

प्रदेश के तेज औद्योगिक विकास के लिए सरकार की कवायद लगातार रंग ला रही है। आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, अमेठी और

आवेदन से लेकर एलओसी तक में फेसलेस सिस्टम का पालन

एटा में इकाइयां लगाने के लिए पांच बड़ी कंपनियों ने ऑनलाइन आवेदन किये थे। इनमें से चार जिलों में बेवेरेज (पेय पदार्थ) और एक में सीमेंट प्लांट स्थापित होगा। तीन इकाइयों में एक-एक हजार करोड़ का निवेश होगा। जबकि शेष दो में 780 और 550 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इकाइयों के विस्तार के साथ निवेश करीब दोगुना हो जाएगा।

नई औद्योगिक नीति में आनलाइन सिस्टम परीक्षा में पास

शासन के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इन पांचों इकाइयों में करीब 2500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के रास्ते खुल गए हैं, जबकि 3500 लोग अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। चार जिलों में पेय पदार्थों की इकाइयां लगने के साथ ही प्रदेश पेय इकाइयों के प्रमुख गढ़ के रूप में उभरेगा।

उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक नीति के बाद पहली बार इन पांचों प्रस्तावों की प्रक्रिया 100 फीसदी आनलाइन की गई है, जो पूरी तरह फेसलेस है। सभी को लेटर आफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी किया जा चुका है। कम से कम 20 हजार करोड़ रुपए की नई इकाइयों को भी लेटर आफ कम्फर्ट जारी हो जाएंगे, प्रक्रिया अंतिम चरण में हैं। ये इकाइयां छोटे जिलों में लग रही हैं। उन्होंने कहा कि फेसलेस सिस्टम से 4500 करोड़ के निवेश को हरी झंडी मिलने से साफ है कि सरकार की नीतियां और क्रियान्वन सही दिशा में हैं।